पैसे पाने के लिए प्रदर्शन

नुकसान से बचने के लिए उसने पूंजी जुटाने की कोशिश की। इससे उसकी रेटिंग खराब हुई और निवेशकों, जमाकर्ताओं ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंक प्रबंधन अपना घाटा छिपाता रहा।

मनीषा भट्ट।

यस बैंक के परेशानी में फंसने से इसके जमाकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। बदहवास हालत में वे बैंक के एटीएम पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पैसे निकल नहीं रहे। शाखाओं में खलबली मची है, वहां भी न पैसे दिए जा रहे हैं, न कोई दूसरी गतिविधि हो रही है। ग्राहकों को अपने पैसे डूबने की आशंका सता रही है। शेयर बाजार पर इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा है।

लोगों के जेहन में कुछ ही समय पहले दिवालिया हुए पीएमसी बैंक की याद ताजा हो गई है। उसके ग्राहकों ने पैसे पाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तक हो गई थी। वैसे रिजर्व बैंक और सरकार इस बार सचेत हैं कि हालात उतने न बिगड़ें।

रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड का संचालन अपने हाथों में लेते हुए इससे महीने में 50 हजार रुपये तक की निकासी सीमा बांध दी है, जबकि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को यस बैंक को खरीद लेने की दिशा में आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है। इधर तीन–चार वर्षों से यस बैंक की वित्तीय सेहत लगातार बिगड़ रही थी। बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया उनमें अधिकतर घाटे में हैं या दिवालिया हो चुकी हैं। पैसे वापस लौटने का सिलसिला टूटा तो बैंक का हाल बिगड़ने लगा।

नुकसान से बचने के लिए उसने पूंजी जुटाने की कोशिश की। इससे उसकी रेटिंग खराब हुई और निवेशकों, जमाकर्ताओं ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंक प्रबंधन अपना घाटा छिपाता रहा।

वित्त वर्ष 2018–19 में यस बैंक ने करीब 3,277 करोड़ रुपये के एनपीए को अपने खाते में दिखाया ही नहीं। रिजर्व बैंक को उसने इस झांसे में रखा कि बैंक को जल्द ही बड़े पैमाने पर निवेश मिलने जा रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के पास निवेश के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। हाल तो अभी भारत के समूचे बैंकिंग सेक्टर का ही बुरा है।

ज्यादातर सरकारी बैंक खस्ताहाल हैं। कुछ बड़े नॉन बैंकिंग फिनांशल इंस्टीट्यूशन एक झटके में डूब गए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी चिंता का विषय है। समस्या की जड़ कुछ हद तक उद्योग और व्यापार की सुस्ती से जुड़ी है, लेकिन कर्ज लेकर न लौटाने की बीमारी हमारे यहां बहुत पुरानी है। इस पर रोक तभी लगेगी जब बैंकों के कर्ज को घर की खेती समझने वालों में खौफ पैदा हो।

पिछले कुछ सालों में विकास को गति देने के नाम पर कई उद्यमियों को आंख मूंदकर कर्ज बांटे गए, जिनमें कई भगोड़े हो चुके हैं। इसके अलावा बैंकों ने कई योजनाओं के तहत भी अंधाधुंध ऋण बांटे हैं, जिनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। अभी यस बैंक के ग्राहकों की जमापूंजी लौटाना सरकार का पहला फर्ज होना चाहिए ताकि उनका विश्वास सिस्टम में बना रहे। अगर आम आदमी का भरोसा अर्थतंत्र से उठ गया तो इसे बहाल करने में लंबा वक्त लगेगा।

श्रद्धालुओं की भीड

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। जेएलएल होटल और हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जयदीप डांग कहते हैं कि भारत के तीर्थ स्थल में हमेशा से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही है लेकिन होटल बनाने वालों को हमेशा से ही उस मांग को पढ़ने और समझने में समय लगा है। इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। इसके लिए आप बोधगया, वाराणसी, धर्मशाला, ऋषिकेश, तिरुपति और अमृतसर को ही देख सकते हैं। यहां आने वाली फ्लाइट बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे स्थलों पर आएंगे जिस कारण होटलों का विस्तार भी होगा। यूरेशिया एट व्यंधम होटल एंड रिसॉर्ट्स के एरिया डायरेक्टर निखिल शर्मा ने कहा कि उनकी होटल श्रृंखला वर्तमान में अमृतसर, वाराणसी और अजमेर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर है जबकि द्वारका, तिरुपति, शिरडी और कटरा में वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं।

संपादकीय

महिला क्रिकेट की नई मंजिल

महिला टी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल नतीजे भले मनमाफिक न आए हों, लेकिन इससे भारतीय टीम की उपलब्धि कम नहीं होती। पूरे टूर्नमेंट में अजेय रही और पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी भारतीय टीम जब रविवार को फाइनल मुकाबले में उसके खिलाफ मैदान में उतरी तो टिक नहीं सकी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 185 रन के विशाल टारगेट के जवाब में वह 99 रन ही बना सकी। बहरहाल, यह तथ्य तो समय की शिला पर अंकित हो ही चुका है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली एशियाई टीम है।

वर्ल्ड चौंपियनशिप भले ही हाथ न आ सकी हो, पर देश में महिला क्रिकेट को मजबूती जरूर मिली है। यह वक्त है एक बार फिर इस सवाल से टकराने का कि हम अपनी महिला क्रिकेटरों को कितना ऊंचा दर्जा देते हैं? क्या उन्हें वे सुविधाएं मिलती हैं, जो चौंपियन बनने लायक मनःस्थिति तैयार करने के लिए जरूरी हैं। ये सवाल सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन दूसरे कई देश इनका जवाब तलाशने में हमसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जिन महिला क्रिकेटरों ने चौंपियनशिप जीती है, उन्हें भी पुरुष क्रिकेटरों के बराबर भुगतान की सहूलियत 2017 में ही मिली और इसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे यहां बराबर भुगतान तो अभी दूर की कौड़ी है, अलबत्ता 2017 में बीसीसीआई ने इनके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने की घोषणा जरूर की। नतीजा यह कि इसके बाद न केवल इन महिला खिलाड़ियों की कमाई बढ़ी बल्कि टीम को बाकायदा एक सपोर्ट यूनिट भी मिला, जिसका मतलब फिजियोथेरैपिस्ट और न्यूट्रीशनिस्ट की सेवाएं उपलब्ध होना था।

सुपर ट्यूजडे यानी मार्च के दूसरे मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए सबसे ज्यादा राज्यों में वोटिंग होती है।

संदेशों की लंबी शृंखला

ममता शाह।

इधर कुछ दिनों से अभिनेता कार्तिक आर्यन के विडियो संदेश वायरल हो रहे हैं। इनमें वह कोरोना वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही पर खीझ दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर संदेशों की लंबी शृंखला है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि वे क्या करें क्या न करें। खास जोर इस पर है कि जहां तक हो सके, सबको अपने घर में ही रहना चाहिए। सुविधा संपन्न लोगों के लिए एकांत एक लग्जरी है, लेकिन उनका क्या जो दिन के हिसाब से कमाते हैं और अपने परिवार के लिए रोजी–रोटी जुटाते हैं?

मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाखों की तादाद में डेली वेज वाले श्रमिक हैं। इनके लिए फंड जुटाना और एक–एक तक मदद पहुंचाना आसान नहीं। इसके लिए सारी फिल्म निर्माता कंपनियों का साथ होना जरूरी है, ताकि सूची बनाने में आसानी हो। प्रोड्यूसर्स असोसिएशन इसके लिए आगे आया है। बड़ी बात यह कि ये लोग गंभीरता से इस काम में लगे हुए हैं। सुधीर मिश्रा ने यह अपील ट्विटर के जरिये 15 मार्च को की थी। उसके बाद ही यह पहल शुरू हुई और फिर आगे बढ़ती गई। मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कितने लोगों तक मदद पहुंची, लेकिन पहुंचनी शुरू हो गई है, इस बात की पक्की सूचना है।

आपदा की स्थिति में सिनेमा से जुड़े लोगों की यह पहल इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जिन्हें देश हीरो मानता है, उनके नागरिक दायित्व भी होते हैं। इसी दायित्व के तहत वे सरकारों के खिलाफ बोलते हैं और पार्टियों के स्थायी वोटर्स की नाराजगी मोल लेते हैं। इससे देशवासियों के एक हिस्से में ऐसी धारणा बनती है कि फिल्मी दुनिया की बड़ी–बड़ी हस्तियां महज पब्लिसिटी के लिए सरकार विरोधी बयान जारी करती हैं। ऐसे में आज के संकटपूर्ण हालात में की गई यह गंभीर और सामयिक पहल भारत में सिनेमा से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।

साल 2011 में एक अमेरिकी फिल्म 'कंटेजिएन' (संक्रमण) आई थी, जिसकी कहानी कुछ उसी तरह के हालात में बनती है, जैसे आज इटली, ईरान और खुद भारत में भी दिखाई पड़ रहे हैं। फिल्म में अपनों को बचाने की कवायद करते हुए लोग हैं और सरकारी प्रयासों के भीतर एक कांस्पिरेसी थियरी का पीछा करता हुआ स्वतंत्र पत्रकार है। मानवता के लिए अपनी निजी सुरक्षा से समझौता करने वाले बड़े लोगों की कोई कथा इस फिल्म में शामिल नहीं है। अलबत्ता छोटे लोगों की एक ऐसी कथा जरूर है, जिसमें एक लेडी डॉक्टर को संक्रमण हो जाता है और वह मरीजों की भीड़ में शामिल हो जाती है।

सूडोकु नवताल- 5298 (सरल)

3	9				1			
5	4			6	8		1	3
		1		7		9	5	
	8	9		5	3		4	7
6	1		4	9		2	3	
	3	4		1		8		
7	5		8	3			2	4
			6				7	9

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5297 का हल

9	6	2	3	4	1	7	5	8
1	4	8	9	7	5	6	2	3
5	7	3	2	6	8	1	4	9
3	2	1	6	9	4	8	7	5
4	8	7	5	1	2	9	3	6
6	9	5	8	3	7	4	1	2
8	3	4	7	2	6	5	9	1
2	1	6	4	5	9	3	8	7
7	5	9	1	8	3	2	6	4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग: सौहार्द कायम करना सबकी जिम्मेदारी

मोहन। दिल्ली दंगे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उसकी जाति या धर्म कुछ भी क्यों न हो। एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आशा है, दोषियों की पहचान कर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए घृणा फैलाने वाले भाषणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अमित शाह ने सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध आर–पार की लड़ाई का आह्वान करते हुए भड़काऊ भाषण दिया। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर तथा अन्य बीजेपी नेताओं के बयान को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना। 4 अप्रैल 1919 को आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद से हिंदू–मुस्लिम और राष्ट्रीय एकता पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उस समय माहौल इतना बिगड़ गया था कि हिंदू–मुस्लिम एकता के लिए गांधीजी ने 1924 में 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 21 दिनों का अनशन किया था।